एफपीओ से कच्चा माल खरीदेंगी अब खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

- अप्रेजल समिति का निर्णय, कृषि क्लस्टर विकास से जुड़ेंगी
- बढ़ेगी किसानों की आय, राज्य में 70 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में उनकी उपज की खपत बढ़ाई जाएगी। ये इकाइयां अब अपने उत्पादों के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से कच्चा माल खरीदेंगी। इसमें भी स्थानीय एफपीओ को वरीयता दी जाएगी। इकाइयों को भारत सरकार के क्लस्टर विकास कार्यक्रम से भी जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल समिति ने यह निर्णय लिया है। अभी तक प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए अलग से कोई दिशा-निर्देश नहीं थे।

राज्य में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 लागू की गई है। इसके तहत फल व सब्जी प्रसंस्करण, दुग्ध प्रसंस्करण, रेडी टू ईट व रेडी टू कुक खाद्य पदार्थ, ब्रेक फास्ट सीरियल्स, स्नैक्स, बेकरी व अन्य खाद्य पदार्थ, अनाज, दाल व तिलहन प्रसंस्करण, अन्य कृषि, बागवानी उत्पाद, मसाले, सोयाबीन, मशरूम प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण, कोको उत्पाद, गुड़ आधारित मूल्यवर्धित उत्पाद, फ्रूट जूस-पल्प से तैयार कार्बोनेटेड पेय पदार्थ आदि इकाइयां स्थापित कराई जा रही हैं।

अब तक 240 इकाइयों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें से 70 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। वहीं एफपीओ के गठन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान में 3995 एफपीओ स्थापित हो चुके हैं।

प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार से किसानों के उत्पादों की खपत बढ़ रही है। सीधे एफपीओ के माध्यम से कच्चे माल की आपूर्ति होने पर किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अभी यह आदेश फ्रोजन फूड और सब्जियों संबंधी प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ही दिया गया है।

दूसरी तरफ क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न फसलों-उत्पादों के लिए विशेष क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। इकाइयों के इनके साथ जुड़ने से क्लस्टर तैयार करने में तेजी आएगी और किसानों को भी सीधे उपज बेचने का अवसर मिल सकेगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सीधी खरीद से जहां इकाइयों को अच्छी गुणवत्ता मिलेगी, वहीं एफपीओ से जुड़े किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा।